

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1503/2013/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड
बनाम्

.....अपीलार्थी.

मैसर्स गणपति क्लर कैम,
1 शिवनगर कमल मार्केट के पीछे, मण्डिया रोड, पाली

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी. ओझा
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.के. पारिक
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

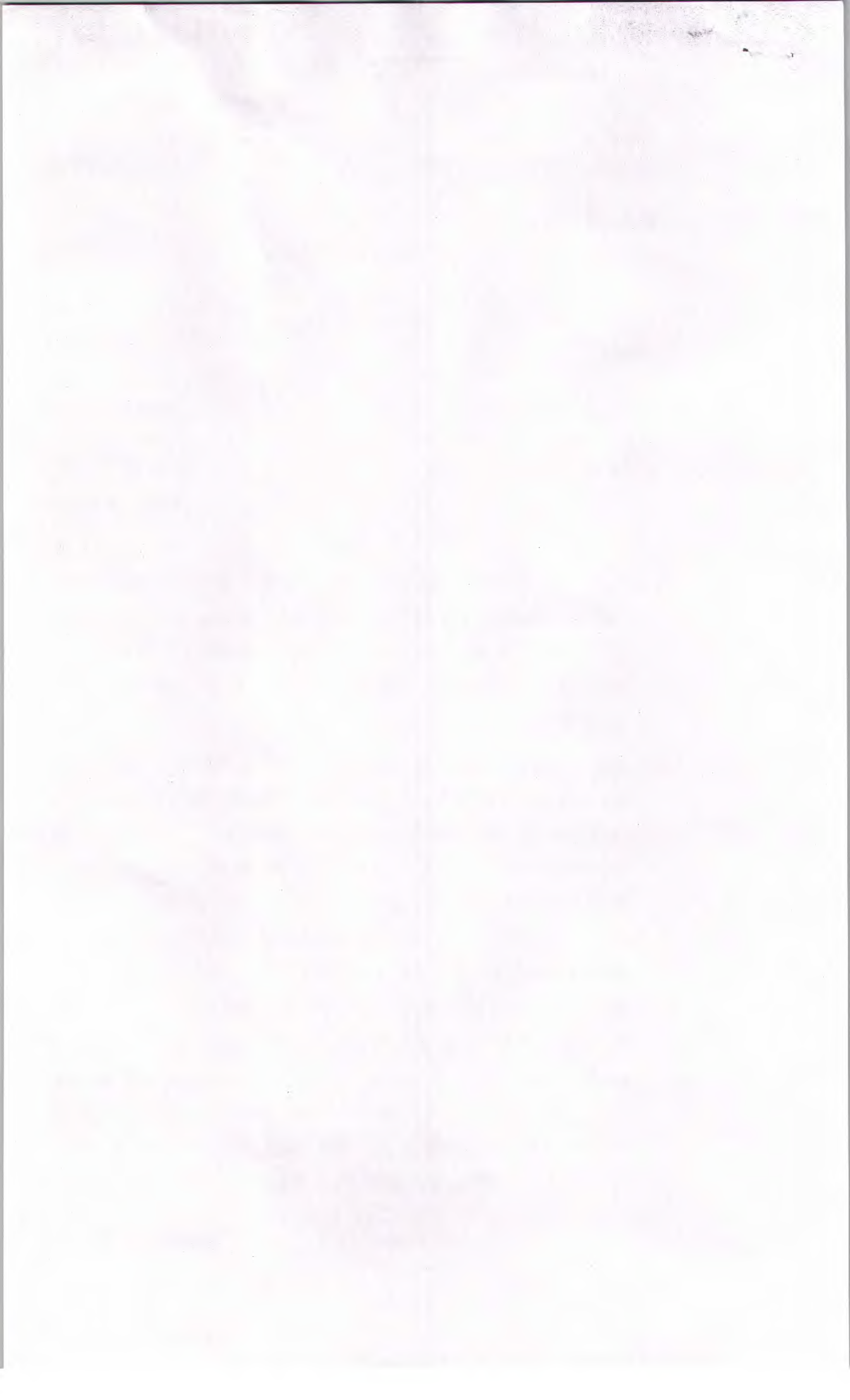
दिनांक : 20.12.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 8/आरवैट/पाली/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 76(6) के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-प्रथम, आबू रोड (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने दिनांक 02.07.2012 को वाहन संख्या GJ 05 AV-0349 को मावल पर चैक करने पर सूरत से पाली के लिये परचून माल परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल के संबन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल, बिल्टी एवं रिक्त फार्म वेट-47 पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को अधिसूचित श्रेणी का मानते हुए परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वेट-47 रिक्त होने के कारण इसे अधिनियम की धारा 76(2) को उल्लंघन माना तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी फर्म के मालिक श्री आशिश सिंघानिया ने जवाब पेश करते हुए नया वेट-47 पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तुत वेट 47 को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल की कीमत 22,57,129/- की 30 प्रतिशत शास्ति रू0 6,77,139/- अधिरोपित की गई। कर

लगातार.....2.

Am. K. P.
20/12/17



निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीली अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मेटल्स के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 05.02.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.02.2013 का खण्डन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी की वस्तु है, जिसके परिवहन के दौरान घोषण पत्र वेट-47 होना आज्ञापक है। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा घोषणा प्रपत्र वेट-47 रिक्त प्रस्तुत किया गया व प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपने जवाब के साथ नया घोषण पत्र वेट-47 पेश किया गया, जो कि अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था, जिससे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया, जो की विधि विरुद्ध है। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक अपने इस कथन के साथ निवेदन किया कि राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.02.2013 को निरस्त की जाये।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा सूरत से पाली के लिये परचूनी का सामान परिवहनित किया गया था। परिवहनित माल के साथ भूलवश रिक्त वेट-47 संलग्न हो गया था जिसे अपनी गलती मानते हुए पुनः नया पूर्ण भरा हुआ वेट 47 जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अमान्य मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है जो अविधिक था। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की सही व्याख्या करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित किया है इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अपीलीय आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा मैसर्स डी.पी. मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 एवं मैसर्स शोरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।
6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मन अध्ययन किया गया।
7. विभागीय पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परचूनी माल परिवहनित

Am:ukul
20/12/17

लगातार.....3.



किया जा रहा था। वक्त चैंकिंग वाहन चालक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का था तथा उसके साथ प्रारूप वैट-47 रिक्त पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म को अधिनियम की धारा 76(2) के नियम 53 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म मालिक द्वारा जवाब पेश करते हुए नया पूर्ण भरा हुआ वैट-47 पेश किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 के आलोक में, आरोपित शास्ति अपास्त की गई।

8. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2001) 124 एस.टी. सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी.पी. मैटल्स में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"..... Once the ingredients of section 78(5) are established, after giving a hearing and complying with the principles of natural justice, there is no discretion not to levy or levy lesser amount of penalty. If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का मैसर्स शेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी S.B. Sales Tax Revision Petition No. 190/2012 निर्णय दिनांक 07.01.2013 के मामले में अनुसरण किया गया जिसके सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है:-

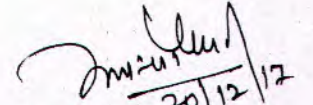
"The Hon'ble supreme court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice regard to alleged contravention/deficiency found in a respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by the themselves indicative of the bonafides of the transit of the goods. Following in the case of DP metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day petitioner assessee having furnished form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under section 76(6) of the RVAT Act."

[Handwritten Signature]
20/12/17

लगातार.....4.



9. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ वेट-47 प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 एवं मैसर्स शोरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होते हैं जिसमें व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र वेट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने से धारा 76 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना गया है। वर्तमान प्रकरण में भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ स्पष्टीकरण देते हुए पूर्ण भरा हुआ घोषणा पत्र वेट 47 प्रस्तुत कर दिए जाने से न्यायिक दृष्टांत डी.पी. मैटल में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में परिवाहनित माल के दस्तावेजों की कमी पूर्ति हो गयी है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2013 विधिसम्मत एवं उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.02.2013 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
10. परिणामस्वरूप उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2013 की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


 (राजीव चौधरी)
 सदस्य

